बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 113 ● नई दिल्ली ● वीरवार 12 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दीवान शुगर मिल में हादसा, चेन में गिरने से मजदूर की मौत

मुरादाबाद। दीवान शुगर मिल में हुए दिल दहला देने वाले एक हादसे में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर मिल की चेन में गन्ने की पुलियां डालते समय अचानक चेन में गिर गया। गन्ने की पुलियों के साथ मजदूर का भी कचूमर बन गया। मजदूर के चेन में गिरने के बाद साथी मजदूर चेन बंद करने के लिए चिल्लाते रहे। कभी मिल के सुपरवाइजर तो कभी ठेकेदार तो कभी सिक्योरिटी गार्ड के पास दौड़ लगाई। लेकिन चेन नहीं रोकी गई। नतीजा ये हुआ कि मिल की चेन में गिरे सुपरवाइजर का शव तक नहीं मिला। चेन में गन्ने की पुलियों के साथ उसकी बॉडी भी पिस गई। हादसे का पता चलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने मिल पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

चिंताजनक- अपराध की राह पर बचपन, राजधानी में दुष्कर्म में लिप्त नाबालिगों की संख्या में 121.21 फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली ।

कभी स्कूल की घंटी और खेल के मैदान से पहचाना जाने वाला बचपन अब अपराध के आंकड़ों में दर्ज हो रहा है। राजधानी दिल्ली में नाबालिगों के हाथों दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में आई 121.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी न सिर्फ कानून व्यवस्था, बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का संकेत है। वर्ष 2024 में दुष्कर्म करने के आरोप में 66 नाबालिग पकड़े गए थे, जबकि 2025 में ये आंकड़ा 146 तक पहुंच गया। सभी तरह के अपराधों में नाबालिगों के शामिल होने की संख्या में 21.67 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। आंकड़ा बताता है कि बच्चों का एक हिस्सा किस तेजी से गलत राह पर फिसल रहा है और यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर हम अपने बच्चों को किस दिशा में छोड़ आए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, जिस दिन अखबार में बाल अपराध से जुड़ी खबर न होती हो। इस विषय में दिल्ली पुलिस, सरकार और बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे एनजीओ को गंभीरता से सोचना और काम करना होगा। दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए ये आंकड़े भारतीय आचार संहिता (बीएनएस) व आईपीसी के तहत दर्ज मामलों का है।

दिल्ली पुलिस एक्ट के मामलों में कुल अपराध में 17.22 फीसदी का इजाफा हुआ है। बीएनएस और आईपीसी के तहत जहां वर्ष 2024 में 2999 नाबालिग पकड़े गए थे, वहीं वर्ष 2025 में पकड़े गए नाबालिगों की संख्या 3649 हो गई। कुल अपराध में वर्ष 2024 में 3270 नाबालिग पकड़े गए थे, जबकि वर्ष 2025 में ये आंकड़ा 3833 तक पहुंच गया।

क्यों भटक रहे हैं नाबालिग

साल 2025 में दिल्ली में नाबालिगों की ओर से किए जा रहे अपराध अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। बढ़ते अपराधों ने पुलिस को सतर्क कर दिया है। दिल्ली में कई जिला पुलिस नाबालिगों को अपराध से दूर करने के लिए कार्यक्रम चला रही है। इसमें

एनजीओ, मनोचिकित्सक की सहायता ली जा रही है। नाबालिगों को अपराध की दुनिया से निकाल कर रोजगार में लगवाया जा रहा है।

घर और स्कूल का छूटता नियंत्रण

कई बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं और घर पर उनकी सही निगरानी नहीं हो पाती। माता-पिता के व्यस्त जीवन और टूटती पारिवारिक संरचना का असर बच्चों के व्यवहार पर साफ दिखने लगा है। गलत संगत में पड़े बच्चे धीरे-धीरे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं और घरवालों को इसका अंदाजा भी नहीं होता।

सोशल मीडिया... दिखावे की दुनिया का खतरनाक प्रभाव

इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कम उम्र के बच्चों को एक ऐसी दुनिया दे दी है, जहां लोकप्रियता और स्टाइल की होड़ चलती रहती है। हथियार दिखाने वाले वीडियो, गैंगस्टर जैसे रील, और 'हीरो' बनने की चाह उन्हें गलत दिशा में धकेलने लगी है।बच्चों को यह समझ ही नहीं आता कि मनोरंजन के नाम पर देखा गया कंटेंट वास्तविक दुनिया में क्या असर डाल सकता है।

नशा, गैंग और अपराध की राह

दिल्ली में सक्रिय कई अपराधी गिरोह अब नाबालिगों को अपने साथ जोड़ने लगे हैं। उन्हें पैसों या नशे का लालच दिया जाता है और फिर छोटे-बड़े अपराध करवाए जाते हैं। गैंगस्टर जानते हैं कि नाबालिगों को कानून के तहत कम सजा मिलती है, इसलिए वे जोखिम भरे काम इन्हीं से करवाते हैं। बाइक चलाने वाले किशोर इन गिरोहों के सबसे आसान शिकार बन जाते हैं।

टूटते संयुक्त परिवार और बढ़ता अकेलापन

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त परिवारों के बिखरने से बच्चों का भावनात्मक संतुलन कमजोर हुआ है। बड़े-बुजुर्गों की सीख, भाई-बहनों का सहारा और परिवार की सामूहिक देखभाल ने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखा था। अब बच्चों के पास न तो सही मार्गदर्शन है और न ही वह माहौल, जो उन्हें गलत कामों से दूर रख सके।

इंटरनेट कंटेंट और किशोरावस्था की जिज्ञासा

किशोर उम्र में आकर्षण और जिज्ञासा स्वाभाविक है, लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री बच्चों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। वे संबंधों, सफलता और प्रसिद्धि को बहुत हल्के में समझने लगते हैं और साथियों को प्रभावित करने के लिए गलत फैसले ले बैठते हैं। दिल्ली पुलिस नाबालिगों को अपराध की दुनिया से निकालने के लिए कई कदम उठा रही है।

पुलिस के साथ ही साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि इन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोका जाए। दिल्ली पुलिस अपनी ओर से नाबालिगों के लिए रूरल प्रतियोगिता, एंटी ड्रग्स क्लब, युवा कार्यक्रम, प्रहरी क्लब के साथ ही बस्तियों में जाकर संपर्क भी करती है। एनजीओ, मनोचिकित्सक और शिक्षकों की सहायता भी ली जाती है। -देवेश चंद्र श्रीवास्तव, विशेष पुलिस आयुक्त(अपराध शाखा) दिल्ली पुलिस।

राहुल गांधी को ईमेल पढ़ने चाहिए... एपस्टीन विवाद पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने LoP राहुल गांधी के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है. दो तरह के लीडर होते हैं. एक वो होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी जिंदगी पब्लिक सर्विस में लगा देते हैं, देश को बदलते हैं. ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में यह पक्का किया है कि देश 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी से चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है. हम अभी चौथे नंबर पर हैं और जल्द ही हम तीसरे सबसे बड़े होंगे. फिर दूसरे लीडर हैं जो कभी-कभी देश आते हैं, कभी-कभी विदेश घूमते हैं, और जब वे पार्लियामेंट में आते हैं, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा, जब कोई कुछ जरूरी बात पेश कर रहा होता था तो वे वॉकआउट कर देते थे और आज, अपनी स्पीच देने के बाद, वे चले गए. आप जानते हैं मैं किस लीडर की बात कर रहा हूं. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जेफरी एपस्टाइन के साथ उनकी बातचीत का उनके खिलाफ लगे आरोपों से कोई लेना-देना नहीं था. मंत्री ने कहा कि उस समय उनका प्राथमिक संपर्क लिंकडइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन से था और उन्होंने इंटरनेट उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट को भारत आने का निमंत्रण दिया था. तीन मिलियन ईमेल में से सिर्फ तीन-चार बार ही उनके नाम का जिक्र हुआ. मैं एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एपस्टीन से मिला था और सिर्फ एक ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था. हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था, जिनका उन पर आरोप है. हमने मेक इन इंडिया के बारे में बात की थी. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जेफरी एपस्टाइन के साथ उनकी बातचीत का उनके खिलाफ लगे आरोपों से कोई लेना-देना नहीं था. मंत्री ने कहा कि उस समय उनका प्राथमिक संपर्क लिंकडइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन से था और उन्होंने इंटरनेट उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट को भारत आने का निमंत्रण दिया था. तीन मिलियन ईमेल में से सिर्फ तीन-चार बार ही उनके नाम का जिक्र हुआ. मैं एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एपस्टीन से मिला था और सिर्फ एक ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था. हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था, जिनका उन पर आरोप है. हमने मेक इन इंडिया के बारे में बात की थी. उन्होंने आगे कहा कि मुझे एपस्टीन की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उनके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं था. एपस्टीन ने मुझे दोमुंहा कहा था. राहुल को ईमेल पढ़ने चाहिए.

कांग्रेस के 20-25 सांसद ओम बिरला के कक्ष में गए और उन्हें गालियां दीं, रिजिजू का विपक्ष पर आरोप

नई दिल्ली ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई सांसद स्पीकर के कक्ष में गए और उनके साथ गाली गलौज की। रिजिजू के अनुसार, इस घटना से स्पीकर ओम बिरला बहुत आहत हैं। पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि उन्होंने खुद इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि करीब 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज की। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि जब यह हो रहा था कि उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे और इसका विरोध करने के जगह अपने सांसदों को और उकसा रहे थे। रिजिजू ने सदन में बोलने को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने एक फैसला दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। उनके मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और वे अपनी इच्छा से बोलेंगे। इस पर रिजिजू ने कहा कि संसद में नियम बहुत साफ हैं, बिना अध्यक्ष की अनुमति कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री भी तभी बोलते हैं जब अध्यक्ष अनुमति देते हैं। हर सदस्य को नियमों का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का स्वभाव बहुत शांत है, वरना इस तरह की घटना पर सख्त कार्रवाई हो सकती थी। बता दें कि यह पूरा विवाद उस समय सामने आया है जब कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर चर्चा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 9 मार्च को हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्ष द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कुछ कमियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का चार बार उल्लेख किया गया है, जो नियमों के अनुसार तकनीकी आपत्ति का कारण बन सकता था। हालांकि, स्पीकर ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि नोटिस में जो भी कमियां हैं, उन्हें ठीक कराया जाए और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए।

संसद से सड़क तक सियासत : भाजपा का आरोप- राहुल का बयान जहरीला, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा- असंसदीय भाषा का इस्तेमाल

नई दिल्ली । भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कभी संसद सत्र लोकतंत्र के सर्वोच्च मानकों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज राहुल गांधी के व्यवहार, भाषा और शैली ने संसदीय मर्यादा को सबसे निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चेतावनी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से झूठे आरोप लगाए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक, संसद में बोलने की एक मर्यादा और शालीन भाषा होती है, जिसका पालन हर सदस्य को करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को सड़कछाप भाषा और आचरण देखना हो, तो वह संसद में विपक्ष के व्यवहार को देख सकता है। भाजपा नेता ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

कांग्रेस हार से बौखलाई हुई- त्रिवेदी

भाजपा सांसद त्रिवेदी ने आगे कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार और संसदीय मर्यादा का पालन न करना दिखाता है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार से बौखला गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी होशो-हवास खो चुके हैं। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को शायद यह भी ध्यान नहीं है कि वे किस पद पर हैं और क्या बोल रहे हैं।

राहुल के देश बेचने वाले बयान पर सुधांशु का पलटवार

त्रिवेदी ने आगे कहा कि राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को बेच दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी को राजनीति और अर्थव्यवस्था की बुनियादी समझ होती, तो वे ऐसा बयान नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाते हुए कहा कि अगर देश बेचने की बात करनी है, तो कांग्रेस को यूपीए सरकार के दौरान आई वोल्कर रिपोर्ट और भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर भी चर्चा करनी चाहिए।

नरवणे की किताब का भी किया जिक्र

इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने जनरल मनोज नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूछ रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन इस मामले में पहले किताब के प्रकाशक और फिर खुद लेखक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से साफ हो गया है कि गलत बयान राहुल गांधी ने ही दिया। भाजपा ने राहुल गांधी के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा और आरोप देश की राजनीति और संसद की गरिमा के लिए ठीक नहीं हैं।

अनुराग ठाकुर ने बजट को बताया 'डेवलपमेंट एक्सप्रेस', बोले- यह 'ए से जी' तक सभी वर्ग के लिए लाभकारी

नई दिल्ली । लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ने इसे देश के विकास और समावेशन को लेकर नया संदेश बताया। ठाकुर ने इसे 'डेवलपमेंट एक्सप्रेस' बताते हुए कहा कि यह सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग के कल्याण की व्यापक दृष्टि है। उन्होंने केंद्रीय बजट को देश के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट सबका जिक्र और सबकी फिक्र के सिद्धांत पर आधारित है और यह केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की व्यापक योजना है। अनुराग ठाकुर ने इसे डेवलपमेंट एक्सप्रेस बताते हुए कहा कि यह बजट देश को तेजी से प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बजट में समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक विनिर्माण और स्टार्टअप्स तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं, किसानों की मदद, डिजिटल नवाचार और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास को समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया है। बजट के ये प्रावधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।अनुराग ठाकुर ने आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। ठाकुर ने आगे कहा कि सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा हुआ निवेश रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ाएगा। साथ ही हरित ऊर्जा, सतत विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि भारत वैश्विक मानकों के अनुसार आगे बढ़ सके। आर्थिक अनुशासन पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और राजकोषीय संयम का संतुलन बनाए रखा गया है। इसके साथ भी भाजपा सांसद ने कहा कि इससे राजकोषीय समेकन, लक्षित सहायता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट ए से जी तक हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है और यह आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

बांग्लादेश में चुनाव

बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद देश छोड़कर भारत आने और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। भारत सहित पड़ोसी देशों की नजरें इन चुनावों पर लगी हुई है। भले ही इन चुनावों को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक चुनाव करार दें लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध शेख हसीना को सत्ता से हटाने और पार्टी के 15 वर्ष के शासन को समाप्त करने वाले जन विद्रोह के बाद हुई कार्रवाई के कारण लगाया गया है। अवामी लीग की अनुपस्थिति में बांग्लादेश के चुनाव एक नौटंकी और धोखा ही है। यह चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने वाले है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी समेत कई पार्टियां मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच ही है। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले जेन-जी यानि छात्र आंदोलन से जन्मी नेशनल सिटिजन पार्टी भी चुनाव मैदान में है। चुनावों के साथ प्रधानमंत्री पद की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है। यह जनमत संग्रह शेख हसीना शासन के तख्तापलट के बाद संवैधानिक सुधार के लिए गठित राष्ट्रीय सर्वसम्मति आयोग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज, जुलाई चार्टर में की गई सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चार्टर की कई सिफारिशों में से एक बांग्लादेश के राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाना है। इसमें वर्तमान संविधान के अनुच्छेद से बंगाली शब्द को हटाकर उसके स्थान पर बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। यद्यपि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बीएनपी के 200 से ज्यादा सीटों पर जीत की भविष्यवाणियां की जा रही है। यानि तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते है। तो दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के गठबंधन की हालत कमजोर मानी जा रही है लेकिन कुछ चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि जमात-ए-इस्लामी चौंकाने वाले परिणाम दे सकती है। चुनावों में राजनीतिक दल भारत विरोधी भावनाओं का जबरदस्त फायदा उठाने की को?शिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया एआई जनरेटड कंटेंट से भरा हुआ है। चुनावी माहौल में क्रिकेट को लेकर जमकर सियासत की जा रही है। सियासी पार्टियां बांग्लादेश की टी-20 वर्ल्ड कप की निराशा को राष्ट्रीय गरिमा और विदेशी हस्तक्षेप पर सवाल खड़े कर रही है। जमात-ए-इस्लामी ने भारत विरोध?को मुद्दा बनाया हुआ है। छात्रों की एनसीपी ने भी भारत विरोध को मुद्दा बनाया है, जिसमें सीमा पर हुई हत्याओं, सीमापार नदियों पर विवाद और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत के कथित हस्तक्षेप शामिल हैं। तारिक रहमान की बीएनपी ने अपने घोषणापत्र में भारत का नाम तो नहीं लिया लेकिन तारिक रहमान के भाषणों में तथाकथित 'मौत का जाल' फरक्का बांध के विकल्प के रूप में पद्मा बैराज के निर्माण का प्रस्ताव कठोर रुख का संकेत दे रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि बांग्लादेश की अगली संसद अल्लाह के कानून से चलेगी या अपना नफा-नुकसान सोच कर। इस समय बांग्लादेश भारत के अहसानों को भुलाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ चुका है। यह चुनाव तय कर देगा कि आखिर बांग्लादेश भारत से संतुलन बनाकर चलेगा या पाकिस्तान और चीन की तरफ जाएगा। इस चुनाव से दक्षिण एशिया शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्याएं हुई, उनके घर और धर्मस्थान जलाए गए। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। शेख हसीना जब से सत्ता से बेदखल होकर भारत में रह रही हैं, तब से भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट को लेकर भी विवाद हुआ। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ संबंध हाल के समय में बेहतर हुए हैं जबकि 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जब एक नया देश बना था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण ही रहे थे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बांग्लादेश के चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन नजर बनाए हुए है। भारत चाहता है कि इस चुनाव के बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जो भारत के साथ रिश्ते सुधार सके। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भारत चाहता है कि अवामी लीग के चुनाव नहीं लड़ने पर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बने। जमात-ए-इस्लामी पार्टी की जीत होने पर भारत की चिंता बढ़ सकती है। जमात-ए-इस्लामी के सत्ता में आने पर सुरक्षा और कट्टरपंथ को लेकर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत दोनों पार्टियों से संपर्क बनाए हुए है। उधर, चीन भी बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। उसने मोहम्मद यूनुस की सरकार में काफी निवेश किया है। उधर, पाकिस्तान भी बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने में लगा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से वीजा के नियम आसान करने पर बात की है। अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान खुलकर बांग्लादेश का साथ दे रहा है। दक्षिण एशिया के पॉवर बैलेंस के लिए बांग्लादेश इसलिए अहम है क्योंकि यह देश भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों चारों मोर्चों पर एक साथ असर डालता है।

दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते बांग्लादेश की स्थिरता दक्षिण एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकती है। विशेषज्ञों ने जनमत संग्रह के औचित्य पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका मानना है कि जनमत संग्रह के विचार और उद्देश्यों के बारे में जनता में बहुत कम समझ है और यह प्रक्रिया तनाव को जन्म दे सकती है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बांग्लादेश का राजनीतिक चरित्र फिलहाल बदला हुआ नजर आ रहा है। अवामी लीग के शासन से भी वहां के लोग खुश नहीं थे लेकिन अवामी लीग की सहभागिता के बिना होने वाले चुनाव में मतदान का प्रतिशत घट सकता है। जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच आतंक का ऐसा माहौल है कि वे वोट डालने नहीं जा सकते। ऐसे में इन चुनावों को निष्पक्ष और ईमानदार कैसे माना जा सकता है।

सम्पादकीय...

चुप्पी के पीछे छिपा सामाजिक संकट

तेज़ी से बदलती जीवनशैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबावों के बीच एक गंभीर समस्या चुपचाप हमारे समाज को घेरती जा रही है–अवसाद। यह वह बीमारी है जो न तो शरीर पर स्पष्ट घाव छोड़ती है और न ही तुरंत दिखाई देती है, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को खोखला कर देती है। चिंता का विषय यह नहीं है कि अवसाद बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि हम आज भी इसे समझने और स्वीकार करने में विफल हैं। अवसाद कोई साधारण उदासी नहीं है। यह कुछ दिनों की निराशा या असफलता से उपजा मनोभाव नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति है, जो व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर निरंतर संघर्ष करता रहता है। आज राज्य के छोटे शहरों और कस्बों तक में अवसाद की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। बेरोज़गारी, आर्थिक अस्थिरता, कृषि संकट, पारिवारिक तनाव और सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव आम नागरिक के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। युवा वर्ग, जो देश का भविष्य माना जाता है, सबसे अधिक इसकी चपेट में दिखाई देता है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, करियर को लेकर अनिश्चितता और सामाजिक तुलना ने युवाओं को मानसिक रूप से थका दिया है। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अवसाद को आज भी कमज़ोरी या नकारात्मक सोच कहकर टाल देता है। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर परिस्थिति में मज़बूत बने रहें। उन्हें रोने, डरने या टूटने की अनुमति नहीं दी जाती। नतीजतन, वे अपनी पीड़ा भीतर दबाए रखते हैं, जो समय के साथ गंभीर रूप ले लेती है। यही कारण है कि आत्महत्या के मामलों में पुरुषों की संख्या अधिक देखी जाती है। महिलाओं के मामले में स्थिति अलग लेकिन उतनी ही चिंताजनक है। उनकी मानसिक पीड़ा को अक्सर भावुकता या स्वभाव का हिस्सा मान लिया जाता है। घरेलू जिम्मेदारियाँ, सामाजिक बंधन और चुप रहने की आदत उनके अवसाद को और गहरा कर देती है। अवसाद के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते। नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, लगातार थकान, आत्मग्लानि, अकेलापन और भविष्य के प्रति निराशा–ये सब संकेत हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। गंभीर स्थिति में व्यक्ति के मन में जीवन समाप्त करने जैसे विचार भी आ सकते हैं, जो समाज के लिए चेतावनी हैं। यह समझना आवश्यक है कि अवसाद का इलाज संभव है। मनोचिकित्सकीय परामर्श, काउंसलिंग और आवश्यकता अनुसार दवाओं से व्यक्ति सामान्य जीवन में लौट सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को। राज्य स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना समय की मांग है।

साझा विरासत का गुलदस्ता है उर्दू भाषा!

फिल्मों गीतों और डायलॉग्स में सदियों से उर्दू का बोलबाला रहा है। एक बार विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधते हुए सुषमा स्वराज ने उर्दू के लहजे में कहा, हज़ारों जवाब चाहिए थे, सवाल एक था, सरकार की नीयत क्या है, सवाल एक था! इस शेर के ज़रिये उन्होंने सरकार की नीतियों और मंशा पर तीखा, लेकिन सुसंस्कृत वार किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उसी तहज़ीब और शायरी के अंदाज़ में जवाब दिया। उन्होंने मिर्ज़ा ग़ालिब की पंक्तियों का सहारा लिया क़र्ज़ की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हां, रंग लाएगी हमारी फ़ाक़ा-मस्ती एक दिन! इस शेर के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सरकार के फैसले तात्कालिक कठिनाइयों के बावजूद भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे। यह बहस दिखाती है कि भारतीय संसद में उर्दू भाषा और शायरी की परंपरा कितनी जीवंत रही है। सुषमा स्वराज की वाक्पटुता और मनमोहन सिंह की विद्वत्ता दोनों ने संसद को बौद्धिक ऊंचाई दी। यह टकराव शोर-शराबे का नहीं, बल्कि संवाद और संस्कृति का उदाहरण था। उर्दू की भारत पर छाप के संबंध में, बकौल, डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, यह भाषा विकसित भारत की पहचान है। उन्होंने बताया कि 5 विकसित भारत और उर्दू के मेल-जोल और सद्भावना का ही परिणाम है कि उर्दू के पत्र-पत्रिकाओं में श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, होली, दीपावली, दशहरा आदि पर खूब लिखा गया है। ईमानदारी की बात तो यह है कि जहां-जहां कोई उर्दू बोलता है, वहां-वहां हिंदुस्तान बोलता है।

उर्दू साझा विरासत और समरसता की भाषा है। यह मज़हब की नहीं, वतन की ज़बान है। उर्दू को अक्सर किसी एक मज़हब से जोड़ दिया जाता है, जबकि हक़ीक़त यह है कि इसकी बुनियाद गंगा-जमुनी तहज़ीब पर है। यह भारत की भाषा है। उर्दू की कई बुनियादी शब्दावलियां जैसे इश्क़, वफ़ा, दर्द, इंसाफ़ ने मज़हब की दीवारें कभी नहीं मानीं। इसी वजह से उर्दू को किसी एक कौम की नहीं, इंसानियत की ज़बान कहा जाता है। ग़ालिब, फ़िराक़, फ़ैज़, फ़राज़, राजिंदर सिंह बेदी, मुंशी प्रेम चंद, ब्रज नारायण चकबस्त, पंडित दया शंकर 'नसीम', तिलोक चंद 'महरूम', आनंद नारायण 'मुल्ला', कृष्ण चंदर, कृष्ण बिहारी नूर आदि हमारी साझा विरासत के ऐसे नाम हैं, जो मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम उर्दू जगत के बड़े नाम हैं। उर्दू के बारे में एक बार जब प्रधानमंत्री को पुस्तक, अबुल कलाम आज़ाद- चंद शख़्सी पहलू प्रदान की गई तो उन्होंने कहा, उर्दू तो हमारे दिल में बसती है! उर्दू को अक्सर किसी एक मज़हब से जोड़ दिया जाता है, जबकि हक़ीक़त यह है कि इसकी बुनियाद गंगा-जमुनी तहज़ीब पर है। उर्दू के विकास और समृद्धि में हिंदू शायरों और लेखकों का योगदान बेहद अहम रहा है। उर्दू एक भाषा होने के साथ-साथ, एक तहज़ीब, परंपरा और प्यार की भाषा भी है, जो भारत की कोख से जन्मी है और हर भारतीय भाषा, क्षेत्र, समाज, धर्म और संस्कृति की सुगंध शामिल है इसमें। यह भारत की आत्मा से जुड़ी भाषा है। यह विकसित भारत की भाषा है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद विकास (नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज) की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इस बात को लेकर हुई कि उर्दू तो अपने जन्म से ही भारत के विकास से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उर्दू से जुड़ी सभी संस्थाओं और संस्थानों को अपने राष्ट्र विकास मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से जोड़ा है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष, डॉ. शम्स इक़बाल के अनुसार उर्दू में देशहित के अतिरिक्त होली, दीपावली, दशहरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण आदि के इकबाल में भी बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जा रहा है। उर्दू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी यह हुई कि इसे मुसलमानों की भाषा समझ लिया गया और इसके विरुद्ध द्वेष बढ़ता गया। इतनी नफ़रत बढ़ी कि इसे विभाजन और पाकिस्तान बनाने का ज़िम्मेदार तक समझ लिया गया, जो कि बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि यदि मुस्लिमों की कोई भाषा है तो। नोट करने की बात यह है कि वह पाकिस्तान, जिसने उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाया है, वहां नाम के ही हिंदी भाषी हैं। इसके पूर्व में पंजाबी तो पश्चिम में बलूची का वर्चस्व है तो मध्य-पूर्व में सिंधी बोली जाती है। उर्दू को अपनी भाषा घोषित कर उसके साथ नाइंसाफी की है। संगोष्ठी में उर्दू भाषा का भविष्य, विकसित भारत 2047 को लेकर था, जिसमें उर्दू से जुड़े लेखकों, शायरों, कथाकारों, नाटककारों आदि ने उर्दू के भूत, वर्तमान और भविष्य को विकसित भारत के विषय से बखूबी जोड़ा। उर्दू, भले ही बाज़ार में, विज्ञापनों में और रोजगार में आज जगह न बना पाई हो, हां देश वासियों और भारत के अंतर्मन में सटीक रूप से जगह बनाने में सक्षम है, क्योंकि जब-जब और जहां, जहां उर्दू मुशायरे हुए हैं, वहां मुस्लिमों से अधिक हिंदुओं की हाज़िरी होती है। ऐसे ही भारतीय संसद में किसी सांसद को अपनी बात दमदार तरीके से कहनी होती है तो उसे उर्दू शेरों द्वारा कहा जाता है। फिल्मों गीतों और डायलॉग्स में सदियों से उर्दू का बोलबाला रहा है। एक बार विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधते हुए सुषमा स्वराज ने उर्दू के लहजे में कहा, हज़ारों जवाब चाहिए थे, सवाल एक था, सरकार की नीयत क्या है, सवाल एक था! इस शेर के ज़रिये उन्होंने सरकार की नीतियों और मंशा पर तीखा, लेकिन सुसंस्कृत वार किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उसी तहज़ीब और शायरी के अंदाज़ में जवाब दिया। उन्होंने मिर्ज़ा ग़ालिब की पंक्तियों का सहारा लिया क़र्ज़ की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हां, रंग लाएगी हमारी फ़ाक़ा-मस्ती एक दिन! इस शेर के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सरकार के फैसले तात्कालिक कठिनाइयों के बावजूद भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे। यह बहस दिखाती है कि भारतीय संसद में उर्दू भाषा और शायरी की परंपरा कितनी जीवंत रही है। सुषमा स्वराज की वाक्पटुता और मनमोहन सिंह की विद्वत्ता दोनों ने संसद को बौद्धिक ऊंचाई दी। यह टकराव शोर-शराबे का नहीं, बल्कि संवाद और संस्कृति का उदाहरण था। उर्दू की भारत पर छाप के संबंध में, बकौल, डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, यह भाषा विकसित भारत की पहचान है। उन्होंने बताया कि 5 विकसित भारत और उर्दू के मेल-जोल और सद्भावना का ही परिणाम है कि उर्दू के पत्र-पत्रिकाओं में श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, होली, दीपावली, दशहरा आदि पर खूब लिखा गया है। ईमानदारी की बात तो यह है कि जहां-जहां कोई उर्दू बोलता है, वहां-वहां हिंदुस्तान बोलता है। राजा राम मोहन रॉय, डा. राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा, मुरली मनोहर जोशी आदि सभी मदरसों के छात्र रहे हैं। आज से ही नहीं शुरू से ही उर्दू ने विकसित और सुरक्षित भारत के संदर्भ में भारत के लिए, चमन, गुलज़ार, गुलशन, बाग-ओ-बहार, गुल-ए-बहार आदि शब्दों से सुसज्जित किया है। आज के दौर में भी उर्दू में भारत की प्रगति को लेकर खूब लिखा जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करुणा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

तिहरे ज़हर कांड का खुलासा-कुख्यात तांत्रिक गिरफ्तार, कार में ज़हर देकर तीन की हत्या

नई दिल्ली ,(ए.के. चौधरी) जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज जतीन नरवाल के नेतृत्व एवं डीसीपी आउटर जिला सचिन शर्मा की निगरानी में बाहरी जिला पुलिस ने एक सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुख्यात स्वयंभू तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने कथित रूप से धनवर्षा कराने का लालच देकर तीन लोगों को कार में ज़हर देकर मौत के घाट उतार दिया।

क्या है पूरा मामला

दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना पश्चिम विहार पूर्व में डीडी नंबर 55-ए के तहत पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें सूचना दी गई कि एक सफेद रंग की कार में तीन लोग बेहोश पड़े हैं। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची।

कार में–

ड्राइवर सीट पर 76 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष,

कार के बाहर 42 वर्षीय पुरुष,

तथा अंदर 40 वर्षीय महिला अचेत अवस्था में पाए गए।

तीनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान

रणधीर (76- निवासी ग्राम बापरोला, दिल्ली

शिव नरेश (42) -प्रॉपर्टी डीलर, निवासी नागली डेयरी, दिल्ली

लक्ष्मी (40) -निवासी

जहांगीरपुरी, दिल्ली परिजनों ने आत्महत्या की आशंका से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।

जांच में क्या सामने आया

कार की तलाशी के दौरान शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, खाली गिलास, मोबाइल फोन, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए।

तकनीकी जांच एवं कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के विश्लेषण से पता चला कि मृतक घटना से एक दिन पहले और घटना वाले दिन लोनी (गाजियाबाद) गए थे, जहाँ उनका संपर्क तांत्रिक कमरुद्दीन से हुआ था।

तकनीकी साक्ष्यों से यह भी पुष्टि हुई कि वापसी के समय कार में एक अतिरिक्त व्यक्ति मौजूद था, जिसकी पहचान कमरुद्दीन के रूप में हुई। वह लोनी से कार में बैठा और घटना स्थल के पास उतर गया।

कैसे रची गई साजिश

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि करीब दो महीने पहले लक्ष्मी का परिचय उससे जहांगीरपुरी निवासी सलीम के माध्यम से हुआ था। बाद में लक्ष्मी ने शिव नरेश और रणधीर को भी उससे मिलवाया।

आरोपी ने तीनों को तांत्रिक अनुष्ठान द्वारा धनवर्षा कराने का झांसा दिया और उनसे 2 लाख रुपये नकद, शराब व कोल्ड ड्रिंक मंगवाई।

आरोप है कि आरोपी पहले से ज़हर मिले लड्डू लेकर आया था। कार यात्रा के दौरान उसने तीनों को शराब और कोल्ड ड्रिंक के साथ वही लड्डू खिलाए।

बेहोश होने के बाद वह नकदी लेकर फरार हो गया, जिससे तीनों की मौत हो गई।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

कमरुद्दीन उर्फ बाबा एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं–

एफआईआर संख्या 31/2014, थाना राजा खेड़ा, धौलपुर (राजस्थान)-हत्या सहित गंभीर धाराएँ

एफआईआर संख्या 105/2025, थाना मक्खनपुर, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)

आगे की कार्रवाई

थाना पश्चिम विहार पूर्व में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तकनीकी एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी स्वयंभू तांत्रिक, बाबाओं या चमत्कार के नाम पर लालच देने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

नरसी मोंजी कॉलेज में 'Insight'26' का भव्य समापन, 10वें संस्करण में 2,000 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी

मुंबई।(सक्षम भारत) नरसी मोंजी कॉलेज का वार्षिक बिज़नेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स फेस्टिवल 'Insight'26' 4 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जिसमें 10वें संस्करण के मौके पर दो हजार से अधिक विद्यार्थियों और पेशेवरों की भागीदारी दर्ज की गई। आयोजकों के अनुसार, इस तीन दिवसीय आयोजन ने अकादमिक सिद्धांतों और उद्योग जगत की वास्तविकताओं के बीच सेतु का काम किया।

फेस्ट प्रतिनिधि ने सच कहूँ संवाददाता को बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम को HPCL ने प्रस्तुत किया, जबकि Uni& India पावर्ड-बाय पार्टनर रहा।

उद्घाटन और 15 प्रमुख आयोजन

4 फरवरी को कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पराग अजगांवकर ने फेस्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहमय बनाया। आयोजकों के अनुसार, तीन दिनों में कुल 15 क्यूरेटेड इवेंट्स आयोजित किए गए।

Insight बिज़नेस कॉन्क्लेव में उद्योग जगत की हस्तियाँ

5 फरवरी को आयोजित Insight Business Conclave (IBC) में उद्यमिता और कॉरपोरेट रणनीति पर चर्चा हुई।

इसमें पद्मश्री सम्मानित शेफ संजय कपूर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अनमोल शर्मा, तथा जेन-ज़ी स्टार्टअप्स DRNK और The Croffle Guys के संस्थापकों ने अपने अनुभव साझा किए।

फेस्ट प्रतिनिधि ने सच कहूँ को बताया कि इन सत्रों से छात्रों को उद्योग की कार्यप्रणाली समझने का प्रत्यक्ष अवसर मिला।

Global Youth Economic Summit रहा समापन आकर्षण

6 फरवरी को Global Youth Economic Summit (GYES) का आयोजन किया गया, जिसमें Prismi& Studios के सह-संस्थापक वत्सल सेठ और साहिल नायर तथा Shark Tank India Season-5 से जुड़ी निवेशक शैली मेहरोत्रा शामिल रहीं। इसके अलावा आयोजित CFO ThinkTank सत्र में LIC के CFO सुनील अग्रवाल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के CFO संदीप बत्रा और कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व ग्रुप हेड नीमिन भट्ट ने वित्तीय नेतृत्व से जुड़े अनुभव साझा किए।

आयोजकों का दावा–छात्रों और उद्योग के बीच मजबूत सेतु

फेस्ट प्रतिनिधि ने सच कहूँ संवाददाता को बताया कि Insight026 ने बॉलीवुड से लेकर कॉरपोरेट क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों को एक मंच पर लाकर छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। आयोजकों के अनुसार, 10वें संस्करण ने न केवल फेस्ट की विरासत को मजबूत किया, बल्कि उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में छात्र समुदाय के जुड़ाव को भी नई दिशा दी।

जनकपुरी गड्ढा हादसा-25 वर्षीय युवक की मौत, दिहाड़ी मज़दूर की गिरफ्तारी पर उठे सवाल

नई दिल्ली (आकाश शक्य)

जनकपुरी इलाके में सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से 25 वर्षीय कमल की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गड्ढे के पास तिरपाल में रहने वाले दिहाड़ी मज़दूर योगेश को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य ज़िम्मेदारों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

क्या है मामला

डीसीपी शरद के अनुसार, घटना के समय एक राहगीर ने सड़क किनारे मौजूद गार्ड को सूचना दी कि गड्ढे में एक बाइक गिरी हुई है।

गार्ड ने यह जानकारी पास ही तिरपाल में रहने वाले मज़दूर योगेश को दी। इसके बाद योगेश ने फोन कर सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को घटना की सूचना दी।

आरोप है कि इसके बाद

सब-कॉन्ट्रैक्टर ने मज़दूर को चुप रहने को कहा और उसे वहाँ से भगा दिया, जबकि वह स्वयं भी मौके से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने पहले सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया और बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा से दिहाड़ी मज़दूर योगेश को हिरासत में लिया।

गिरफ्तारी पर सवाल

मज़दूर योगेश पर आरोप है कि उसने घटना की सूचना सीधे पुलिस को नहीं दी। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि–

यदि पुलिस को सूचना न देने का अपराध है, तो राहगीर और गार्ड पर भी कार्रवाई क्यों नहीं?

जिस गड्ढे में युवक की जान गई, उसके लिए ज़िम्मेदार बड़े ठेकेदार,

दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारी,

और सड़क की निगरानी करने वाले विभागों पर अब तक कोई आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मामले में कमज़ोर और गरीब मज़दूर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि जिनके पास पैसा और सत्ता है, वे कानून से दूर हैं।

गरीब भुगतेगा सज़ा?

सूत्रों के अनुसार, सब-कॉन्ट्रैक्टर भी जल्द ज़मानत पर बाहर आ सकता है, जबकि दिहाड़ी मज़दूर योगेश के पास न तो पैसे हैं, न कानूनी सहायता, न ही कोई प्रभावशाली पैरवी।

सवाल यह है कि 25 साल के कमल की मौत की सज़ा क्या एक गरीब मज़दूर भुगतेगा, जबकि लापरवाही से सड़क खोदकर छोड़ देने वाले बड़े ज़िम्मेदार खुले घूमते रहेंगे?

प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

यह मामला एक बार फिर दिल्ली की सड़कों की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ़ गरीबों के लिए है?

राहुल बोले-स्पीकर सर आप मेरी पार्टी में थे, स्पीकर का जवाब-मेरी बात मानते तो आप विपक्ष में नहीं बैठे होते

नई दिल्ली। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल के बीच मजेदार नोकझोंक दिखी. दरअसल, जब राहुल गांधी आम बजट पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो जगदंबिका पाल को कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं. इसलिए मैं आपको स्पेशल फेवर करूंगा. राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि आपका दिल हमारे लिए धड़क रहा है. इसपर पाल ने कहा कि ये चार्ज है. इसके बाद पाल ने कहा कि ये कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि आपकी आसन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? यहां कुमारी शैलजा भी इस चेयर पर बैठती हैं. राहुल गांधी ने फिर कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं. इसलिए मैं ज्यादा आक्रामक नहीं रहूंगा. इसपर नाराज होकर जगदंबिका पाल ने कहा कि आप मेरे बारे में बार-बार क्यों बोल रहे हैं. इसपर राहुल ने कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं. मुझे पता है कि आपका दिल हमारी तरफ है. इसके बाद जगदंबिका पाल ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं आपकी पार्टी का एक्स मेंबर हूं न? अभी मैं सभापति के रूप में हूं. पाल ने कहा कि लेकिन आप हमारी बात मानते तो वहां नहीं बैठे होते. पाल ने कहा कि आप वहां इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी. मैं आपको सलाह दे रहा हूं. आपको सही दिशा में बढ़ना चाहिए. पाल ने कहा कि आपके पास अभी भी समय है, सही दिशा में जाने के लिए. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सही तरीके से समझौते नहीं किए. राहुल ने कहा कि सरकार ने किसानों और कारोबारियों का ख्याल नहीं रखा. उन्होंने कहा कि सरकार ने 150 करोड़ लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक लीक, दिल्ली पुलिस ने प्रकाशक पेंगुइन को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आगामी किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं और जवाब मांगे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज फोरम्स पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता उल्लंघन से जुड़ा है, जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल में केस दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी ऑनलाइन कैसे पहुंची, इसमें किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका हो सकती है, और क्या इसमें कॉपीराइट या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पैसों की बारिश के लालच में कैसे फंस गया 200 करोड़ का मालिक, पीरागढ़ी केस में बड़ा सवाल?

नई दिल्ली। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार के अंदर तीन मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में एक बाबा को गिरफ्तार किया है. इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि रणधीर नाम मृतक काफी अमीर था और उसे हर महीने करीब 18-20 लाख रुपये किराया आता था. दिल्ली के बापरोला गांव का रहने वाला था, बताया जा रहा है कि वो करीब 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक था. इसके बाद भी कथित तौर पर धनवर्षा के चक्कर में 2 लाख रुपये लेकर पकड़ा गया बाबा कमरुद्दीन के पास गया था. बाबा ने उसकी हत्या करने के बाद 2 लाख रुपये लेकर भाग गया था. पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिला दी थी. जिसके बाद कार में सवार रणधीर, शिव नरेश सिंह और लक्ष्मी देवी की मौत हो गई. रणधीर ड्राइविंग सीट पर बैठा था जबकि बाकी दो पीछे की सीट पर बैठे थे. सूत्रों ने बताया कि कमरुद्दीन ने रणधीर को पैसों की बारिश का झांसा दिया था. इसी झांसे में रणधीर फंस गया. पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने कहा था कि पैसों की बारिश के लिए उसे एक महिला की भी जरूरत होगी. आरोपी बाबा ने कहा कि ऐसी महिला चाहिए जिसके बाल लंबे हों.

मेगा परियोजनाओं की प्रगति की सख्त निगरानी कर समयबद्ध पूरा करें कार्य - मुख्यमंत्री सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित स्टेट प्रगति डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही मेगा परियोजनाओं की प्रगति की कड़ी निगरानी की जाए।

और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं को स्टेट प्रगति डैशबोर्ड पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए, जिससे विभिन्न स्तरों पर

उनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करवाने के लिए लगातार निगरानी की जाए। श्री सैनी ने परियोजनाओं में देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि जिन एजेंसियों को निर्माण कार्य अलॉट किए गए है उन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन एजेंसियों की वजह से निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है, उनके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित आठ मेगा परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को इनका लाभ शीघ्र मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा, श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, आयुक्त एवं सचिव वित्त श्री मोहम्मद शायन, मुख्य प्रशासक एचएसवीपी श्री चंदर शेखर खरे, विशेष सचिव (मॉनिटरिंग एवं समन्वय) डॉ. प्रियंका सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टेट प्रगति डैशबोर्ड की बैठक में 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की

भारत का डेटा बेचा गया? राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार

नई दिल्ली । देश की राजनीति में एक बार फिर डेटा सुरक्षा और अमेरिका-भारत व्यापार समझौता चर्चा के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के डेटा के साथ समझौता किए जाने के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा भारत का डेटा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षित है। देश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों के अपने-अपने नियम हैं। आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सरकार का स्पष्ट कहना है कि देश की डेटा संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है।

हम डेटा के मामले में ताकतवर हैं- राहुल गांधी

बुधवार को लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारत की ताकत को जनता और डेटा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों का देश सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि डेटा के विशाल भंडार के कारण भी वैश्विक शक्ति बन सकता है। उन्होंने एआई की तुलना इंजन से करते हुए कहा कि जैसे इंजन को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही एआई को डेटा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पेट्रोल यानी डेटा नहीं है, तो एआई बेकार है। राहुल गांधी के मुताबिक, इस समय दुनिया में दो बड़े डेटा पूल हैं भारत और चीन। ऐसे में भारत के पास वैश्विक शक्ति बनने का सुनहरा अवसर है।

एआई युग और बदलती वैश्विक राजनीति

राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया अब एक या दो सुपरपावर के दौर से आगे बढ़कर बहु-ध्रुवीय व्यवस्था की ओर जा रही है। उन्होंने अमेरिकी वर्चस्व और डॉलर की स्थिति को चुनौती मिलते हुए बताया। उनका कहना था कि एआई के इस दौर में पारंपरिक आईटी इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और कई इंजीनियरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है।

अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने हालिया अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने भारत के डेटा ट्रेड पर अमेरिका को नियंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को अपनी सुपरपावर स्थिति बनाए रखनी है, तो उसके लिए भारत का डेटा सबसे अहम है। जब हम समझौते की टेबल पर जाते है, तो हम अपने ही लोगों को उस टेबल पर रख देते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका को डेटा तक मुक्त पहुंच दे दी है और सोर्स कोड साझा न करने की छूट भी दी है।

किसानों, ऊर्जा और टैरिफ पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ट्रेड डील के जरिए भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए गए है, जिससे भारतीय कृषकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने ऊर्जा खरीद, टैरिफ नीति और आर्थिक फैसलों पर भी अमेरिका के प्रभाव का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह देश के हितों के खिलाफ है।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएंगे- किरेन रिजिजू

नई दिल्ली।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए हम विशेषाधिकार नोटिस दायर करने जा रहे है. उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा और राजसभा में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के बहुत स्पष्ट नियम है. जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप की पुष्टि भी करनी होगी. मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को अपने द्वारा दिए गए प्वाइंट्स को प्रमाणित करने के लिए सदन के पटल पर बुलाया जाए. राहुल गांधी ने बेकार और झूठे आरोप लगाए है. सदन के पटल पर मैंने राहुल गांधी से उनके दावों के आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था. उन्होंने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार और भ्रामक आरोप लगाए, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय हितों को बेच दिया है. दूसरे, उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उनके खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप लगाए.यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है. इसलिए, मैं स्पीकर के समक्ष आवश्यक नोटिस दाखिल करना चाहता हूं. किरेन रिजिजू आज शाम 5 बजे तक राहुल गांधी को समय देंगे उसके बाद इसे लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे.

राहुल-जगदंबिका पाल के बीच नोकझोंक

राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि आपका दिल हमारे लिए धड़क रहा है. इसपर पाल ने कहा कि ये चार्ज है. इसके बाद पाल ने कहा कि ये कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि आपकी आसन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? यहां कुमारी शैलजा भी इस चेयर पर बैठती है.

सुप्रीम कोर्ट में असम सीएम हिमंत सरमा के खिलाफ एक और याचिका सूचीबद्ध, नफरती भाषण देने का आरोप

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। चार लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री पर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। यह याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने दायर की थी। इसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र है। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को एक समुदाय की ओर राइफल से निशाना लगाते और गोली चलाते दिखाया गया है। बुधवार को कोर्ट से कहा गया कि नई याचिका को भी उसी मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा, हम देखेंगे। नई याचिका पूर्व प्रोफेसर हिरेन गोहेन, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरेकृष्ण डेका, वरिष्ठ पत्रकार परेश चंद्र मलाकर और वरिष्ठ वकील शांतनु बोरठाकुर ने दायर की है।

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्व सरमा) ने कई बार विवादित बयान दिए हैं। इन बयानों से असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और हिंसा भड़क सकती है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों और मीडिया बातचीत में धर्म, भाषा, जन्मस्थान और निवास के आधार पर दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया।

याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए मिया और बांग्लादेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

भारतीय वायु सेना नई पीढ़ी के और अधिक विमान शामिल करने की इच्छुक - उपप्रमुख

नई दिल्ली । वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायु सेना अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और भी अधिक विमानों को शामिल करने को इच्छुक है। कपूर वायु शक्ति अभ्यास से पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। राफेल के बारे में उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल निश्चित रूप से अन्य नायकों के साथ-साथ एक नायक था। जी हां, राफेल इन दिनों एक चर्चित शब्द बन चुका है; यह निश्चित रूप से चर्चा के केंद्र में है। वायुसेना के उपप्रमुख ने कहा, वायुसेना और भी कई एमआरएफए (बहु-भूमिका लड़ाकू विमान) को शामिल करने का इच्छुक है, चाहे वह राफेल हो या कोई अन्य विमान, इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। और इस संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कपूर ने कहा, भारतीय वायु सेना अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और अधिक विमान शामिल करने के लिए उत्सुक है, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने इसी कार्यक्रम में बताया कि आगामी वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, एसयू-30, मिग-29, तेजस, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के सफल योगदान को प्रदर्शित करेंगे।

पूर्व विधायक बलराज कुंडू से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी: रोहित गोदारा गैंग का नाम आया सामने, वॉयस मैसेज भेजा

महम । रोहतक जिले के महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू से फोन पर वॉयस मैसेज के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। घटना के बाद कुंडू ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल को शिकायत भेजी है। जिस नंबर से यह मैसेज आया था, वह भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि बलराज कुंडू ने 2019 में महम से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 5 साल तक विधायक रहे. वह एक व्यवसायी भी है। उन्हें हाल ही में 10 तारीख को शाम 6 बजकर 39 मिनट पर एक फोन आया, जिसके साथ एक वॉयस मैसेज भी था। इस मैसेज में दो दिन के भीतर 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है।

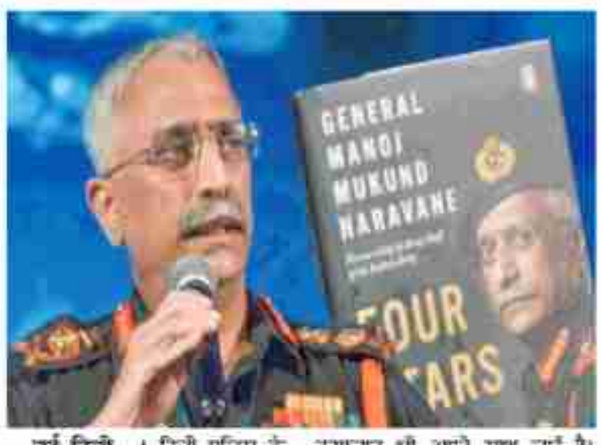

नोटिस के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस के दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस, ढाई घंटे तक की जांच

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक को लेकर दर्ज मामले में और सीक्रेट एक्ट व कॉपी राइट की धाराएं भी जोड़ी है। वहीं, दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को गुरुग्राम में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के ऑफिस में पहुंची और करीब ढाई घंटे तक जांच पड़ताल की। टीम वहां से कुछ कागजात भी अपने साथ लाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस ऐसे समय में जारी किया गया, जब पुस्तक की स्थिति और अनधिकृत संस्करणों के कथित अवैध प्रसार के विरोध में दावे किए जा रहे हैं, जिसमें प्रकाशक, पूर्व सेना प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां एक व्यापक सार्वजनिक विवाद में शामिल हो गई हैं। पुलिस के अनुसार विशेष प्रकोष्ठ ने नोटिस के माध्यम से प्रकाशक से औपचारिक रूप से संपर्क कर कई सवाल पूछे हैं और उनके विस्तृत जवाब मांगे है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से कई सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब मांगे गए हैं। यह कदम उन रिपोर्ट के मद्देनजर उठाया गया है जिनमें दावा किया गया है कि नरवणे के संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पांडुलिपि प्रकाशन से पहले डिजिटल और अन्य प्रारूपों में अवैध रूप से संभवत प्रसारित की गई। पुलिस ने बताया कि पांडुलिपि के अनधिकृत प्रसार के संबंध में लगे आरोपों के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब (फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी) के ऑनलाइन लीक और अनधिकृत सर्कुलेशन को लेकर दर्ज मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और कॉपीराइट अधिनियम की धाराएं जोड़ दी हैं। पुलिस ने यह कदम तब उठाया जब बिना जरूरी मंजूरी के किताब के अंश सोशल मीडिया पर साझा किए गए। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है कि संवेदनशील पांडुलिपि कैसे सार्वजनिक हुई।

पेश किया गया 9.13 लाख करोड़ का बजट, प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट; नई योजनाओं की घोषणा

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा है।

बजट राज्य को दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। बजट में 1.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित है, बल्कि 50 से अधिक नई योजनाओं के जरिए महिलाओं, युवाओं, किसानों, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रखा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प' और 'विजन-2047' की दिशा में निर्णायक कदम बताया। पिछले वर्षों में बजट का आकार लगातार बढ़ा है। 2017-18 में जहां बजट लगभग 3.85 लाख करोड़ था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 9.13 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। यानी नौ वर्षों में बजट आकार दोगुने से भी अधिक हो

गया है। यह बजट आकार, पूंजीगत निवेश पर जोर, नई योजनाओं की संख्या और महिला-युवा-किसान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ राज्य को तेज आर्थिक वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब फोकस 'संतुलित, समावेशी और सतत विकास' पर है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में बच्चों के लिए बड़े एलान किए हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी में नई योजनाएं के लिए 750 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। युवाओं को टैबलेट बांटे जाएंगे। सुरेश खन्ना ने बताया कि फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22167 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए 6195 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। छात्राओं को 400 करोड़ से स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केन्दों पर

"यूपी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। यह बजट 9.13 लाख करोड़ का रहा। इस बजट में चुनावी झलक देखने को मिली।

23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।स्वामी विवेकानन्द युवा-सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निशुल्क वितरित किए जा चुके है। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

राहुल गांधी ने कहा- सरकार ने भारत माता को बेच दिया

लोकसभा : एपस्टीन फाइल्स, ट्रंप की धौंस से लेकर अमेरिका के दबदबे तक... राहुल गांधी ने इन बातों पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज आम बजट 2026 पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल काफी आक्रामक तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने बजट को आज के दौर के मुताबिक नाकाफी बताया। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के बढ़ते दबदबे और भारत के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते पर अपनी बात सदन में रखी। राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल्स से लेकर अमेरिका की धौंस का मुद्दा उठाया। साथ ही सरकार को घेरते हुए अदाणी-अंबानी को लेकर भी जमकर घेरा।

राहुल बोले-एपस्टीन, 3 मिलियन फाइलें अभी भी बंद

राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां, भारत माता को बेच दिया है।

मजेदार बात यह है कि मुझे पता है कि आम हालात में प्रधानमंत्री भारत को नहीं बेचते। आपको पता है उन्होंने भारत क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते है। वो बातें है- एपस्टीन। 3 मिलियन फाइलें अभी भी बंद है।

डाटा को लेकर क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पाकिस्तान के बराबर नहीं बनेंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने तय किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हमें इस बारे में कुछ कहना होगा। अब क्या हुआ?

आपने एक ट्रेड डील की है, जो चीज 21वीं सदी में भारत को बदलने वाली है, जो चीज हमें 21वीं सदी में सुपरपावर बनाने वाली है। मोदी सरकार ने हमारे डाटा के साथ यही किया है। हम अपने डिजिटल ट्रेड रूल्स पर कंट्रोल छोड़ देते हैं। नंबर दो, डाटा लोकलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। नंबर तीन, अमेरिका में फ्री डाटा फ्लो। नंबर चार, डिजिटल टैक्स पर लिमिट। नंबर पांच, किसी भी सोर्स कोड को बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। उन्हें मुस्कुराना बहुत पसंद है। जो कोई भी चाहे, बड़ी टैक्स कंपनी को 20 साल की फ्री टैक्स हॉलिडे। आपने डेटा पर यही किया है।

अमेरिका संग बराबर की शर्तें रखनी होंगी

इसी के साथ राहुल गांधी ने व्यापार समझौते को लेकर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता। मैं आपको बताता हूं कि हम क्या कहते। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ट्रंप से कहते, इस समीकरण में सबसे जरूरी चीज इंडियन डाटा है। आप अपना डॉलर बचाना चाहते हैं? हम आपके दोस्त हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके डॉलर को बचाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखें कि अगर आप अपना डॉलर बचाना चाहते है, तो सबसे बड़ी एसेट जो आपके डॉलर को बचा सकती है, वह इंडियन लोगों के पास है। वह है डाटा। आपको हमसे बातचीत करने में बराबरी से शर्तें रखनी होंगी।

अमेरिका फैसला करता है हम किससे तेल खरीदेंगे- राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ताकतवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 18 फीसदी टैरिफ लग रहा है। अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करता है तो उस पर शून्य टैरिफ

लगेगा। यानी हमारे कपड़ा उद्योग तो गया। अब अमेरिका फैसला करता है कि हम किससे तेल खरीदेंगे। रूस और ईरान किससे खरीदेंगे, यह सब फैसले अमेरिका करता है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते। राहुल ने कहा कि शुरुआत में अमेरिका हम पर तीन फीसदी टैरिफ लगाता था, अब वह 18 फीसदी टैरिफ लगाता है। अमेरिका से हमारा आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर होने वाला है।

उन्होंने हमसे कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। हमने उनसे कई प्रतिबद्धताएं की हैं। हमारे टैरिफ बढ़ गए हैं, उन पर लगने वाले टैरिफ 16 से शून्य पर आ गए हैं।

पीएम की आंखों में डर दिख रहा है - राहुल

राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि आपने हमारे किसानों को कुचलने के लिए अमेरिकी कृषकों के लिए भारत के बाजार खोल दिए हैं। यानी हम एक तूफान झेल रहे हैं। आप यह स्वीकार कर रहे हैं। क्या मतलब है कि अमेरिका हमसे कहे कि आप किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं। क्या मतलब है अगर अमेरिका हमसे कहे कि आप पर इतना टैरिफ कब बढ़ेगा और कब कम होगा। यानी उन्होंने ऊर्जा और वित्त को हथियार बना लिया है। आप किस तरह इस सदन में आकर इस ट्रेड डील के बारे में बात कर सकते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती। मैं कह रहा हूं कि आपने भारत को बेच दिया है। हमारी भारत माता को बेच दिया है। क्या आपको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री ने भारत को इसलिए बेच दिया, क्योंकि उनकी गर्दन पर चोक (फंदा) कर लिया गया है। इनकी गर्दन फंसी है, इसलिए देश को बेच रहे है। पीएम की आंखों में डर दिख रहा है।

अदाणी-अंबानी पर सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अदाणी-अंबानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बजट के केंद्र में देखेंगे तो मैंने कहा था जिजित्सु में चोक दिखती है, राजनीति में नहीं दिखती। हमारे बजट के केंद्र में अदाणी की कंपनी एक साधारण कंपनी नहीं है। समझिए उनके खिलाफ अमेरिका में जो केस है, वह प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना है। भारत पर नहीं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एक व्यापारी अनिल अंबानी है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह जेल में क्यों नहीं है? वजह यह है कि उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहूंगा कि उन्हें एपस्टीन से किसने मिलवाया। मुझे पता है कि उन्हें किसने मिलवाया, और हरदीप पुरी जानते है कि उन्हें किसने मिलवाया।

यह सिर्फ पीएम का सरेंडर नहीं..., बोले राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा कि पूरी बात यह है कि मैं नहीं मानता कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल है, वह अमेरिका के साथ ऐसी कोई डील साइन करेंगे, जब तक उन पर कोई शिकंजा न हो। टैरिफ के लिए हमने उन्हें अपना डाटा दे दिया। हमने डिजिटल टैक्स पर भी लिमिट लगा दी है। उन्हें 20 साल का डिजिटल टैक्स छूट दे दी है। मैं नहीं मानता कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा करेगा, लॉजिक हो नहीं है। यह पूरा सरेंडर है। यह एक त्रासदी है क्योंकि यह सिर्फ पीएम का सरेंडर नहीं है, यह 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है। यह भाजपा के वित्तीय ढांचे को बचाना चाहते हैं। मैंने जितने भी आरोप लगाए है, उनका सत्यापन तुरंत कर दूंगा। इसका सबूत अमेरिका के न्याय मंत्रालय की तरफ से रिलीज की गई फाइल्स में है। उनमें हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम है।

अमेरिका के दबदबे को चुनौती

संसद में राहुल गांधी ने कहा, मैं आर्थिक सर्वे देख रहा था और मुझे उसमें दो बातें मिलीं, ठोस बातें, गहरी बातें जो मुझे पसंद आईं। पहली बात कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां भू-राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका के दबदबे को चीन, रूस, और दूसरी ताकतें चुनौती दे रही है। दूसरी बात यह है कि हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारों की दुनिया में रह रहे हैं। वे यहां जो मुख्य बात कह रहे है, वह यह है कि हम स्थिरता की दुनिया से अस्थिरता की दुनिया में जा रहे हैं।

भारत के हितों से समझौता किया, राहुल का आरोप

राहुल गांधी ने दावों पर कहा कि मेरे पास अपने आरोपों का सत्यापन करने के लिए यहीं पर कागजात मौजूद हैं। मैं इन्हें पेश कर सकता हूं। मंत्रीजी ने मुझसे कहा है कि मैं सबूत पेश करूं, लेकिन आप (स्पीकर) मुझे करने नहीं दे रहे। भारत को बेच दिया गया है। भारत का डाटा बेच दिया गया है। किसानों के हितों को बेच दिया गया है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, बिजनेसों और हमारे सुरक्षाबलों और ऊर्जा हितों को बेच दिया गया है।

बजट में आज की चुनौतियों पर बात ही नहीं

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इस वक्त दुनिया के पास डाटा के दो पूल हैं- भारत का डाटा पूल (1.4 अरब लोगों का) और चीन (वहां भी इतनी ही जनसंख्या है)। यानी हम डाटा के मामले में ताकतवर हैं। हमारी दूसरी ताकत है हमारे किसान, जो खाना देते हैं। हमारे पास खाना प्रचुर मात्रा में है। तीसरा- हमें देश को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। इन तीनों को बचाना आधुनिक समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बजट इन चीजों की पहचान तो करता है। वह कहता है कि हम खतरनाक समय में जा रहे हैं। वह जानता है कि भू-राजनीतिक स्थिति खतरनाक हो रही है। ऊर्जा और वित्त को हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन बजट में इसके लिए कोई हल नहीं है। बजट सिर्फ किसी आम बजट की तरह ही है। इसमें इनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया गया है। बजट में आज की चुनौतियों पर बात ही नहीं है।